एआई से बढ़ी छंटनी, भारत का स्थान दूसरा

- एआई बना छंटनी का बड़ा कारण
- कंपनियां तेजी से ऑटोमेशन अपना रही हैं
- पारंपरिक टेक नौकरियां हो रही कम

नई दिल्ली, 5 जुलाई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल ने वैश्विक टेक उद्योग में रोजगार की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. कंपनियां अब लागत कम करने, काम की गति बढ़ाने और उत्पादकता सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर एआई आधारित टूल्स और ऑटोमेशन तकनीकों को अपना रही हैं. इसका सीधा असर टेक सेक्टर में नौकरियों पर दिखाई दे रहा है.

टेक उद्योग में छंटनी पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 तक दुनिया भर में 1.28 लाख से अधिक टेक कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त हो चुकी हैं. यह आंकड़ा पिछले पूरे वर्ष 2025 में हुई कुल छंटनी (1.25 लाख) से भी अधिक है, जो इस बात का संकेत है कि स्थिति तेजी से बदल रही है.

रिपोर्ट बताती है कि 2026 की शुरुआत से ही टेक कंपनियों में छंटनी का सिलसिला तेज हो गया है. कंपनियां अपने संचालन मॉडल को एआई-केंद्रित बना रही हैं, जिसके चलते कई पारंपरिक भूमिकाओं की आवश्यकता कम होती जा रही है. खासकर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग और मैन्युअल ऑपरेशंस से जुड़े पदों पर इसका सीधा असर पड़ा है.

देशवार आंकड़ों के अनुसार, इस पूरी छंटनी अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है, जहां कुल छंटनी का बड़ा हिस्सा दर्ज किया गया. इसके बाद भारत का स्थान आता है, जो छंटनी के मामले में दूसरे नंबर पर है.

> एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, बल्कि काम करने के तरीके को भी पूरी तरह बदल रहा है. कई कंपनियां अब छोटे लेकिन हाई-स्किल्ड टीमों के साथ काम कर रही हैं, जो एआई टूल्स की मदद से अधिक उत्पादन कर सकती हैं. हालांकि, इसका नुकसान उन कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है जो पुराने स्किल सेट पर निर्भर थे आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि वैश्विक स्तर पर टेक इंडस्ट्री में अस्थिरता लगातार बनी हुई है.

चावल, गेहूं, चीनी में साप्ताहिक तेजी

नयी दिल्ली, 5 जुलाई. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल का औसत भाव बढ़ गया. चावल के साथ गेहूं और चीनी में भी तेजी रही. वहीं, दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख देखा गया. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 17 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,918 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं भी 16 रुपये महंगा हुआ और 2,797 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बोला गया. आटे का भाव तीन रुपये चढ़कर 3,257 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. सप्ताह के दौरान उड़द दाल की औसत कीमत 34 रुपये और तुअर दाल की 27 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. वहीं, मूंग दाल 15 रुपये और चना दाल सात रुपये सस्ती हुई. मसूर दाल की कीमत पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर स्थिर रही.

सीतारमण ने कादाराश परमाणु भट्टी का किया दौरा

स्वच्छ ऊर्जा और फ्यूजन तकनीक पर जोर

नयी दिल्ली, 5 जुलाई वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र कादाराश में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर केंद्रित महत्वाकांक्षी अंतराष्ट्रीय परियोजना - इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) का दौरा किया जो भारत सहित विभिन्न देशों के सहयोग से विकसित की जा रही है .यह जानकारी वित्त मंत्रालय से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दी.

वित्त मंत्री के समक्ष वहां इस उस परियोजना में भारत के योगदान पर एक प्रस्तुति दी गयी. यह प्रस्तुति वहां कार्यरत एलेन बेकूले और कट्टालाई रामचंद्रन श्रीराम ने दी. उसके बाद उन्होंने गाइड के साथ आईटीईआर परिसर का दौरा किया. उन्होंने रिएक्टर के क्लीनिंग हॉल, असेंबली हॉल और टोकामाक पिट का अवलोकन किया तथा वहां की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की.

श्रीमती सीतारमण ने पिछले दो दशकों से इस परियोजना में योगदान दे रहे भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सहयोगियों तथा एलएंडटी , इनॉक्स इंडिया , टीसीएस, टीसीई , एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ सहित अन्य प्रमुख भारतीय उद्योगों के उत्कृष्ट कार्य की भी सराहना की. आईटीईआर' एक विशाल अंतरराष्ट्रीय सहयोग परियोजना है, जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक टोकामाक परमाणु संलयन (न्यूक्लियर फ्यूज़न) रिएक्टर विकसित करना है. इस परियोजना में भारत सहित सात प्रमुख सदस्य देश शामिल हैं.

> वित्त मंत्री ने आईटीईआर परियोजना में कार्यरत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की समर्पित भावना की सराहना की. उन्होंने कहा कि दुनिया की यह सबसे महत्वाकांक्षी परमाणु 'संलयन' ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है और भविष्य के लिए स्वच्छ, परिस्थितिकी की दृष्टि से स्वस्थ एवं लगभग असीमित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

वैश्विक कारकों से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई, 5 जुलाई घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में बाजार की दिशा वैश्विक कारकों पर निर्भर करेगी.

अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते के लिए जारी वार्ता, विदेशी शेयर बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव पर निवेशकों की नजर होगी. घरेलू स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस के पहली तिमाही के परिणाम भी अगले सप्ताह 09 जुलाई को आने हैं.पिछले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को शेयर बाजारों में गिरावट रही जबकि अगले तीन दिन अच्छी तेजी देखी गयी. बीएसई का सेंसेक्स 663.44 अंक (0.86 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त में शुक्रवार को 77,763 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी सप्ताह के दौरान 214.85 अंक यानी 0.89 प्रतिशत चढ़कर 24,270.85 अंक पर पहुंच गया. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.11 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.05 प्रतिशत की साप्ताहिक मजबूती के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स की 30 में 20 कंपनियों में गत सप्ताह तेजी रही. इटरनल का शेयर 10.24 प्रतिशत चढ़ गया. बजाज फिनसर्व में 7.46 फीसदी, बजाज फाइनेंस में 5.42, मारुति सुजुकी में 4.53 और अडानी पोर्ट्स में 4.34 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी.

टाइटन का शेयर 3.98 प्रतिशत, ट्रेंट का 3.84, एशियन पेंट्स का 3.53, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 3.49 और भारती एयरटेल का 3.24 प्रतिशत चढ़ गया.

> नुकसान उठाने वालों में एलएंडटी का शेयर सप्ताह के दौरान 4.58 प्रतिशत टूट गया. कोटक महिंद्रा बैंक में 3.01 फीसदी, एक्सिस बैंक में 2.47, टेक महिंद्रा में 1.83, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.38 और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.06 फीसदी की गिरावट रही. भारतीय स्टेट बैंक, इंडिगो, टीसीएस और आईटीसी के शेयर भी लाल निशान में रहे.

भारत-ब्रिटेन व्यापार नियमों को मिली मंजूरी

इससे तीसरे देशों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी

नई दिल्ली , 05 जुलाई भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने समझौते के तहत 'उत्पत्ति के नियम' (रूल्स ऑफ ओरिजिन) अधिसूचित कर दिए हैं, जो 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे.

इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक रियायतों का लाभ केवल उन्हीं वस्तुओं को मिले, जिनका वास्तविक उत्पादन दोनों देशों में हुआ हो. इससे तीसरे देशों के उत्पादों को गलत तरीके से शुल्क छूट का लाभ लेने से रोका जा सकेगा और द्विपक्षीय व्यापार अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष बनेगा.

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, व्यापार समझौते के तहत शुल्क में छूट पाने के लिए प्रत्येक उत्पाद के साथ 'उत्पत्ति प्रमाणपत्र' अनिवार्य होगा. यह प्रमाणपत्र केवल भारत और ब्रिटेन की अधिकृत एजेंसियां ही जारी करेंगी. इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि संबंधित उत्पाद समझौते में निर्धारित मूल मानकों को पूरा करता है या नहीं. यदि कोई उत्पाद इन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो उसे मुक्त व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली सीमा शुल्क रियायत का लाभ नहीं मिलेगा.

सरकार का मानना है कि नए नियमों से व्यापार समझौते के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगेगी. कई बार तीसरे देशों के उत्पाद मामूली बदलाव कर भारत या ब्रिटेन के उत्पाद के रूप में पेश किए जाते हैं, ताकि शुल्क छूट का लाभ मिल सके.

> इस व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. समझौते के तहत ब्रिटेन में भारत के करीब **99 प्रतिशत निर्यात** को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी. इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते-चप्पल, समुद्री उत्पाद, खिलौने, खेल सामग्री, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी. वहीं ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑर्गेनिक रसायन जैसे क्षेत्रों के लिए भी ब्रिटेन का बाजार अधिक सुलभ होगा.

यूएई पहुंचीं कश्मीर की प्रीमियम चेरी-आलूबुखारा

नई दिल्ली, 05 जुलाई जम्मू-कश्मीर के बागवानी क्षेत्र को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी और दुबई के लिए प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली निर्यात खेप का आभासी शुभारंभ किया.

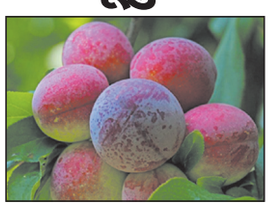

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, शोपियां और पुलवामा जिलों के किसानों से एकत्र किए गए एक मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टोन फ्रूट्स की यह खेप न केवल जम्मू-कश्मीर के बागवानी उत्पादों की बढ़ती निर्यात क्षमता को दर्शाती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्रीमियम फलों की बढ़ती मांग का भी प्रमाण है.=

इस उपलब्धि पर किसानों और निर्यातकों को बधाई देते हुए एपीईडीए के अध्यक्ष अभिषेक देव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर उत्कृष्ट बागवानी उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और यहां से उच्च गुणवत्ता वाले फलों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं.

भूटान ने नहीं ठुकराया ई20 पेट्रोल

नई दिल्ली, 5 जुलाई भूटान द्वारा भारत से ई20 पेट्रोल खरीदने से इनकार करने की खबरों पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह विराम लगा दिया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्टों में किया गया यह दावा पूरी तरह गलत है.

मंत्रालय के अनुसार, भारत की किसी भी तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) ने भूटान को ई20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव भेजा ही नहीं है. ऐसे में यह कहना कि भूटान ने भारत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तथ्यहीन है.

पिछले कुछ दिनों से यह खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि भूटान ने भारत से ई20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया है. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि भूटान के ईंधन भंडारण ढांचे में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. बताया गया कि ई20 पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल नमी को आसानी से सोख लेता है, जिससे इसके भंडारण के लिए विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है.

होर्मुज जलमार्ग में फिर बढ़ा तनाव

नई दिल्ली, 05 जुलाई . फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर तनाव के केंद्र में आ गया है. हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने को लेकर हुए समझौते के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओमान के तट के पास कम से कम आठ तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों को अचानक अपना रास्ता बदलकर यू-टर्न लेना पड़ा, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है.

पीएफ के नए नियम, बदला गणित

कर्मचारी और नियोक्ता के लिए 1,800-1,800 रुपये का अनिवार्य मासिक अंशदान

नई दिल्ली, 05 जुलाई कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित ईपीएफ योजना-2026 के प्रभाव में आने के बाद अब पीएफ कटौती का वर्षों पुराना गणित बदल गया है.

29 जून 2026 से लागू नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के लिए हर महीने 1,800-1,800 रुपये का अनिवार्य अंशदान तय किया गया है. पहले दोनों पक्षों को कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (डीए) का 12-12 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा करना अनिवार्य था. इस बदलाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी बढ़ेगी या भविष्य की बचत कम हो जाएगी.

अब तक पीएफ की कटौती कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर होती थी. यानी जिसकी बेसिक सैलरी अधिक होती थी, उसके वेतन से हर महीने ज्यादा रकम पीएफ में जमा होती थी. इससे कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी कम जरूर होती थी, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार होता था.

नई व्यवस्था में सरकार ने अनिवार्य अंशदान को एक निश्चित राशि तक सीमित कर दिया है. अब कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों को न्यूनतम 1,800 रुपये प्रति माह जमा करना होगा.

समाचार विशेष

देखो राहुल, अखिलेश, दिग्गी ; राम का नाम बदनाम ना करो

राकेश शर्मा

नातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं ने 500 वर्ष इंतजार किया तब राम मंदिर का निर्माण हुआ.कुछ धन पशुओं ने भगवान के चढ़ावे में गड़बड़ी की जिसकी सजा कानून और ऊपर वाला दोनों उन्हें देंगे.पर आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि वह लोग जो लगातार राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे वह आज सामने निकलकर फिर राम और राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आज राम मंदिर की चिंता हो रही है वह अखिलेश यादव जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने निर्दोष,निरीह, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं जिसमें कई निर्दोष कारसेवकों की जान चली गई थी.आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव,प्रियंका वाड्रा, अरविन्द केजरीवाल ने राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था.

वोटों की राजनीति के लिए हमेशा राम के खिलाफ खड़े रहने वाले यह विपक्ष के नेता आज फिर अपनी वोटों की रोटियां सेकने के लिए आज फिर मैदान में उतरे हुए हैं. सनातन धर्म का विरोध यह विपक्ष के नेता हमेशा से करते आ रहे हैं और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनका पोषण और संरक्षण भी यह विपक्ष के नेता हमेशा से करते आ रहे हैं.जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा था तो वहां तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने राम को काल्पनिक पात्र कहा था.कोई विपक्ष का नेता वहां टॉयलेट निर्माण की बात कर रहा था,कोई वहां लाइब्रेरी,स्कूल खोलने की बात कर रहा था.मंदिर निर्माण से लाखों करोड़ों विश्व में सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था से खिलवाड़ करने का और अपमान करने का कोई भी मौका इन विपक्ष के दल के नेताओं ने नहीं छोड़ा था.

केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी वह लगातार हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ कानून बनाने का काम कर रही थी,लोग आज भी इसे नहीं भूले हैं कि किस तरह इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज के नेतृत्व में गायों की रक्षा के लिए किए जा रहे आंदोलन में दिल्ली में गोलियां चलवाई थीं जिसमें कई मासूम साधु-संतों के प्राण चले गए थे.

> विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राम मंदिर की आड़ में कीचड़ उछलने का जो प्रयास आज विपक्ष के नेता कर रहे हैं उसे देश की जनता जान रही है. राम मंदिर चढ़ावे में जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई कानून करेगा. उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तोड़ने का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है. दिग्विजय सिंह के चंदा वापस मांगने पर मध्य प्रदेश के एक नागरिक ने दिग्विजय सिंह ने जो चंदा दिया उन्हें वह देने का प्रस्ताव दिया है इससे यह सिद्ध होता है कि जनता की आस्था राम और राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है पर विपक्ष के नेता आज फिर अपना मुखौटा उतार कर जनता के बीच जाकर राम का नाम बदनाम कर रहे हैं.

विपक्ष की एकता कसौटी पर

नई दिल्ली. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मसले पर विपक्षी पार्टियों ने एकता दिखाई है. इसका खूब प्रचार भी किया गया है.

कांग्रेस महासचिव और प्रचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आठ जून को हुई 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में 21 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे लेकिन उसमें पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक जब एसआईआर को लेकर चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई तो उस पर 23 पार्टियों के नेताओं ने दस्तखत किए. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इससे आगे बढ़ कर बताया कि डीएमके और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी चीफ जस्टिस को लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत किया है.

गौरतलब है कि दो साल के बाद आठ जून को विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी. लेकिन उसमें डीएमके और आप ने हिस्सा नहीं लिया है. डीएमके इस बात से नाराज है कि कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही उससे नाता तोड़ कर फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके से गठबंधन कर लिया.

सुधीर शर्मा का फिर दिखा जलवा

धर्मशाला बीडीसी पर भाजपा का कब्जा

धर्मशाला. नगर निगम धर्मशाला में मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत के बाद अब विकास खंड धर्मशाला (बीडीसी) में भी भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज कर राजनीतिक बढ़त को और मजबूत कर लिया है.

वहीं, धर्मशाला में लगातार दूसरी बड़ी जीत को भाजपा खेमे में सुधीर शर्मा की संगठनात्मक पकड़ और रणनीति की सफलता के रूप में देखा जा रहा है.

गुरुवार को बीडीओ ऑफिस धर्मशाला में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुए. एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न की देखरेख में हुई प्रक्रिया में सभी 18 निर्वाचित बीडीसी सदस्यों ने भाग लिया. नामांकन, नाम वापसी और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए. चेयरमैन पद पर भाजपा समर्थित नरवाना खास वार्ड-6 के आलोक कुमार ने 18 में से 12 मत हासिल कर अपने प्रतिद्वंद्वी सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू को 6 मतों से हराया.

भेदभाव से ऊपर उठकर करेंगे विकास

वहीं, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक कुमार और उपाध्यक्ष सरोज कुमारी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि वे राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर पूरे विकास खंड में समान रूप से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. इस जीत के साथ धर्मशाला की स्थानीय राजनीति में भाजपा ने एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति का संदेश दिया है. नगर निगम धर्मशाला के बाद अब ब्लॉक समिति पर भी कब्जा कर भाजपा ने आगामी राजनीतिक मुकाबलों से पहले अपना मनोबल और संगठनात्मक ताकत दोनों प्रदर्शित कर दिए हैं.

विशेष | क्या बनेंगी सुप्रिया सुले? शरद पवार की गुगली पर टिकी नजर

मोदी कैबिनेट में मंत्री या कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव!

मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगी या फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव. महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय होने के बाद पार्टी के एनडीए में जाने की चर्चाओं ने राजनीति को गरमा दिया है.

चर्चा है कि शरद पवार ने कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) दोनों के साथ समानांतर बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि उनकी पार्टी एनसीपी (एसपी) महाराष्ट्र में विपक्षी सांसदों और विधायकों को तोड़ने की कोशिशों के बीच अंदरूनी फूट का सामना कर रही है. शरद पवार के पास अभी 8 सांसद हैं. चर्चा है कि पांच सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं. ऐसे में शरद पवार जल्द कोई फैसला ले सकते हैं.

यह चर्चा ऐसे वक्त पर सामने आई है जब पीएम मोदी के जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव करने की चर्चा जोरों पर है.

अगर शरद पवार एनसीपी के एनडीए में जाने का फैसला लेते हैं तो सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनेंगी. इसके साथ ही उनके सांसदों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी.

अगर शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हैं, जिसकी बातचीत होने का दावा किया जा रहा है तो सुप्रिया सुले कांग्रेस में ताकतवर राष्ट्रीय महासचिव की पोस्ट दी जा सकती है. विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पवार एनसीपी का कांग्रेस के साथ विलय तभी करने को तैयार हैं जब उनकी बेटी सुप्रिया

लोकसभा की वरिष्ठ सांसद हैं सुप्रिया

शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अभी बारामती से लोकसभा सांसद हैं. सुप्रिया सुले की उम्र 57 वर्ष है. उनकी जन्मतिथि 30 जून 1969 है. सुप्रिया ने राजनीतिक सफर की शुरुआत राज्यसभा से की थी. वह 2006 राज्यसभा सदस्य बनी थीं. 2009 में वह पहली बार अपने पारिवारिक गढ़ बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी. इसके बाद 2014, 2019 और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामती सीट से लगातार जीत हासिल की है.